Legislation for Women Workers in Fish Processing Industry

712. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to enact any legislation to help the women workers in Fish Processing Industry;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of welfare measures to safeguard the interest of the workers in sea food processing industry?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Marine Products Export Development Authority (MPEDA) gives assistance to the seafood processors to upgrade their facilities to achieve equivalency with the European and US standards by which the workers get better facilities in the processing plants. Extension Trainings are being given to pre processing and processing workers for hygenic handling of fishery products.

Migrant Labours in Agriculture and Fish Processing Industry

713. SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the details regarding the migrant labours in Agriculture and Fish Processing Industry;

(b) the steps taken by Government to enusre their labour rights; and

(c) whether Government propose to enact any legislation to help the said workers?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) As per Census of India 1991, out of total number of 7,69,56,052 migrant workers by place of last residence the number of migrant agriculture labour is 2,15,12,218. The details of migrant labourers in Fish Processing Industry is not tabulated.

(b) and (c) The Government have already enacted Inter-State Migrant Workman (Regulation of employment and conditions of service) Act, 1979 to ensure their labour rights. The Act provides for regulation of their service conditions and certain welfare measures i.e. wages, displacement allowance, journey allowance etc. apart from this, these workers are covered under various labour laws i.e. Minimum Wages Act, 1948, Equal Remuneration Act, 1971, Workmen's Compensation Act, 1923, etc.

बाल श्रमिकों का शोषण

714. **श्रीमती सरोज दुबे:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बाल श्रमिकों का शोषण कम करने के लिए सरकार की योजना क्या है;

(ख) ऐसे बाल श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनकी शोषण के कारण मृत्यु हो गई है या इसके परिणामस्वरूप वे किसी गंभीर रोग का शिकार होकर अपाहिज हो गए है, और

(ग) इस शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) देश में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची के भाग क और ख में वर्णित 13 व्यवसायों और 51 प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों की रोजगार की परिस्थितियों को विनियमित किया जाता है। सरकार का प्रयास बाल श्रम और अन्य सभी संबंधित कानूनों को इस तरीके से कार्यान्वित करना है जिससे बच्चों के शोषण पर रोक लगायी जा सके। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बाल नियोजन करने वाले नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है। उक्त